



# भारत का गज़त

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 201]

नई दिल्ली, दुधवार, अक्टूबर 21, 1992/ग्रामिन 29, 1914

No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1992/ASVINA 29, 1914

इस भाग को किसी पछ संख्या दी जाती है जिससे इसके यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1992

फा. स. 4/11/91—ई. पी. ओ. आई. —विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष पूर्णी निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :

सरकार ने विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया है जिन्हें एलडब्ल्यू अधिसूचित किया जाता है:

विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त :

1.1 ये मार्गदर्शी सिद्धान्त विदेश में संयुक्त उद्यम तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (जिन्हें बाद में विदेशी कंपनियों कहा जाएगा 1) में भारतीय पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश पर लागू होते हैं। ये नई प्रवर्तित विदेशी कंपनियों में भारतीय पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश तथा विवादन विदेशी कंपनियों में भारतीय पक्षों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करते के लिए लागू होते हैं।

1.2 ऐसी विदेशी कंपनी, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश किये जाने का प्रस्ताव है, को औद्योगिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक अवधारणा सेवा कियकालाप या होटल में या पर्यटन उद्योग में लगाया जा सकता है।

1.3 ये मार्गदर्शी सिद्धान्त विदेशी कंपनियों में भारतीय पक्षों द्वारा पीर्ट फोलियों निवेश निक्षेप पर लागू नहीं होते। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त वित्तीय अंत जैसे बैंकिंग बीमा, आपसी निधियां वित्तीय और और इसी प्रकार की सेवाओं में जो विदेशी कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश पर भी लागू नहीं होते उनमें सामलों पर उचित प्राविकारी द्वारा पूँजीबुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

2. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रयोगन के लिए:

(क) "प्रत्यक्ष निवेश" का अभिन्नाम उत्त कंपनी में दीर्घावधि प्राप्त करते के उद्देश्य से विदेशी कंपनियों की इकिवटी पूँजी में भारतीय पक्ष द्वारा निवेश होता। इकिवटी की रकम के अतिरिक्त ऐसा दीर्घावधि सहित विदेशी कंपनी के निवेशक भंडत में प्रतिनिधित्व तथा तकनीको जानकारी, पूँजी गति वस्तुओं, संघटकों, कर्जों सामग्री आदि तथा विदेशी कंपनी के वार्ताकाल कार्यालयों के साध्यम से परिलक्षित होना चाहिए।

(अ) "मेजबान देश" का तात्पर्य उस देश से होगा जिसमें प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनी स्थापित, पंजीकृत अथवा निर्मित होती है।

(ब) "भारतीय पक्ष" का तात्पर्य भारत के कानूनों के अनुसार स्थापित और सरकारी सरकारी लिमिटेड कंपनी होगा। जब एक से अधिक भारतीय निकाय निगम विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश करती है, तो सभी निकाय निगम भिलकर भारतीय पक्ष बनते हैं।

(च) "संयुक्त उद्यम" का तात्पर्य होगा मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार स्थापित पंजीकृत अथवा निर्मित ऐसी विदेशी कंपनी जिसमें भारतीय पक्ष में प्रत्यक्ष निवेश किया हो चाहे इस निवेश में शेयरधारिता अधिक हो अथवा कम।

(द) "पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी" का तात्पर्य होगा मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार स्थापित पंजीकृत अथवा निर्मित ऐसी विदेशी कंपनी जिसकी समस्त इकाइयाँ भेदभाव पूरी भारतीय पक्ष के स्वामित्व में हों।

3. भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन पक्ष निर्वाचित प्रबल में निर्वाचित दसवेंजों के साथ वाणिज्य मंबालय (विदेश निवेश प्रभाग) भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110001 को प्रस्तुत किए जाएँ।

#### 4. 1 श्रेणी "क" — स्वतः अनुमोदन मामले

विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन पक्ष को प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर स्वतः अनुमोदन के लिए तभी पात्र होगा जब निम्न-निर्धित दो मानदण्ड पूरे किए जाएँ।

मानदण्ड—1

भारतीय पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष निवेश का कुल मूल्य 2 (दो) मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का न हो, जिसमें भारतीय पक्ष द्वारा नकद अंशदान 500,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक न हो। प्रत्यक्ष निवेश का शेष अंश पूर्णतः पूंजीकरण के जरिए या आंशिक रूप में निम्ननिर्धित में पूरा किया जाएँ।

(क) विदेशी कंपनी को सञ्चाहि किए गए भारत में निर्मित संवर्धन योगीरी, उपस्कर और संघटक;

(ख) भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कंपनी को निर्वाचित किए गए माल की आय;

(ग) तकनीकी जानकारी, परामर्श, प्रबंध संबंधी या अन्य तेवरं दों के के लिए विदेशी कंपनी से प्राप्त शुल्क, रायलटो कमीशन या अन्य हकदारियाँ।

मानदण्ड—2

भारतीय पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के पूर्णतया नकद अंशदान होने के मामले में नकद अंशदान 500,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक न हो।

4. 1. 1 भारतीय पक्ष को उसी विदेशी कंपनी के संबंध में स्वतः अनुमोदन की यह सुविधा तीन वित्तीय वर्ष के बालक में, जिसमें वह वित्तीय दृष्टि शामिल है जिसमें निवेश किया गया है, केवल एक बार उपलब्ध होगी।

#### 4. 2 श्रेणी "1" प्रत्यक्ष निवेश के अन्य मामले

प्रत्यक्ष निवेश के अन्य सभी मामलों पर वाणिज्य मंबालय में अंतर-मंबालयी समिति गुणवत्तु के आधार पर विचार करते और अविवाचन प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर निर्णय देती उपर्युक्त श्रेणी "क" में बताए गए निवेश के स्त्रोतों के अन्तर्वाद, श्रेणी "ख" के तहत प्रत्यक्ष निवेश में निम्न-निर्धित स्त्रोतों को भी शामिल किया जाए।

#### (क) उपर्युक्त प्राविकारियों द्वारा अनुमोदन के प्रधारीन वाहन व्यवस्था

(ख) "प्रबल" निविधि से भुगतान निवेशी निधियाँ अवश्य तभी होती हैं जब मेजबान देश में निर्वाचित से आरा या निवेशी से लाभ कुछ ऐसे कारणों से भारतीय पक्ष को हक्कतातिरित नहीं किए जाते हैं जो भारतीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर होते हैं।

(ग) निवेश का कोई अन्य ऐसे स्त्रोत विस्ते भारत सरकार की अनुमति मिल जाए।

4. 3 श्रेणी "ख" के तहत अवेदनत्व पर विवार करते समय अंतर-मंबालयी समिति ने अन्य बातों के मार्ग-नाम निम्ननिर्धित को पुरी तरह घास में रखा है,

(क) भारतीय और विदेशी पक्षों को वित्तीय स्थिति, साझा और अवसाय चलाने का पिछला रिकार्ड;

(ख) भारतीय पक्ष का निर्वाचित में अनुभव और तिक्कारा रिकार्ड तथा इसकी नियांतोन्मुखता;

(ग) प्रस्तुत निवेश को प्रत्यक्षतः वर्धकमता

(घ) भारतीय पक्ष के स्रोत निवेश मूल्य और कार्य को माला के संदर्भ में प्रस्तावित निवेश की माला और विदेश स्थित उद्यम का आकार; और

(क) विदेशी भुवन आय, दिवसीय व्यापार, सूचन प्रोधोगिकी हस्तान्तरण भारत में उपलब्ध नहीं होने वाले कच्चे माल और मध्यवर्ती पदार्थों के जिए पहुंच तथा इसी तरह को अन्य बातों को देखते हुए देश को लाभ।

4. 4 उपर्युक्त "क" दोनों श्रेणियों के तहत भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश के जिए अन्य अंशदान के लिए पुरानी या मरम्मत की गई विदेशी मरीनरी सञ्चाहि की जा सकती है।

5. प्रत्यक्ष निवेश मेजबान देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा, यह अपेक्षा की जाती है कि जहाँ तक संभव हो संयुक्त उद्यम में स्थानीय पक्षों, स्थानीय विकास बैंकों और स्थानीय संस्थानों से महसूब किया जाए जब तक विरोध के लिए सुइकारण न हो, विदेशी संवर्धकों या भागीदारों के रूप में प्रलग-अलग व्यक्तियों के सहयोग की ग्रोस्ट्रिंग नहीं किया जाता है।

6. 1 जिस संयुक्त उद्यम में भारतीय पक्ष का प्रस्ताव की इकाइयों द्वारा वित्तीय व्यापार है, उनके संबंध में भारतीय पक्ष वाणिज्य मंबालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक को संयुक्त उद्यम द्वारा लिए गए निम्ननिर्धित नियंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत करेगा और ये जोड़े मेजबान देश को स्थानीय वित्तीयों के अनुसार संयुक्त उद्यम के द्वारा धारियों/प्रोत्साहकों निवेश द्वारा दिये गये अनुमोदन के 30 दिन के भीतर संज्ञेजा;

(i) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के लिए मूलतः अनुमोदित अंशदान से भिन्न कोई कार्बकलाप आरम्भ करना;

- (ii) किसी अन्य कम्नों को इकिटी पूँजी में भागीदार होना;
- (iii) एक विदेशी गोण कम्नों के रूप में किसी सहायक कम्नों अथवा पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्नों को बढ़ावा देना;
- (iv) अपने प्राधिकृत अथवा जारी, शेयर पूँजी द्वाचे या उसके शेयर धारिता पैटेन्ट में परिवर्तन करना।

6.2 जिस संयुक्त उद्यम के मामले में भारतीय पक्ष की अधिकांश इकिटी शेयर धारियों हैं प्रथवा किसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्नों के मामले में भारतीय पक्ष भारत सरकार को पहले सूचित किये बिना विदेशी कम्नों द्वारा लिए जा रहे निम्नलिखित विनियोगों पर सहमति देसकते हैं:

- (i) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश के लिए मूलतः अनुमोदित कार्यकलाप से भिन्न कोई कार्यकलाप आरम्भ करना;
- (ii) किसी अन्य कम्नों की इकिटी पूँजी में भागीदार होना;
- (iii) एक विदेशी गोण कम्नों के रूप में किसी सहायक कम्नों अवैदा पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्नों को बढ़ावा देना;
- (iv) अपने प्राधिकृत अथवा जारी शेयर पूँजी द्वाचे या उसके शेयर धारिता पैटेन्ट में परिवर्तन करना।

उपर्युक्त निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों।

(क) भारतीय पक्ष ने विदेशी कम्नों से प्राप्त होने वाली सभी हकदारियों स्वदेश भेज नी हो, इनमें लाभांश, फीस तथा रायलिटी भी शामिल हैं और इसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित किया गया हो।

(ख) भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कम्नों को किए गए नियर्यों के संबंध में विदेशी कम्नों की ओर 180 दिन से पुरानी उत्तरकी कोई राशि बकाया न हो;

(ग) भारतीय पक्ष ने भारत से नकद मंगाने की कोई नई मांग न की हो; और

(घ) भारतीय पक्ष के मूलतः स्थापित संयुक्त उद्यम में अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्नों में इकिटी शेयर धारिता की प्रतिशतता कम नहीं की गई हो जब तक कि मेजबान देश की विधियों के अनुसार ऐसा करना जरुरी न हो।

भारतीय पक्ष वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक को संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्नों द्वारा लिए गए नियर्यों के व्यापे प्रस्तुत करेगा। उक्त व्योरे मेजबान देश की स्थानीय विधियों के अनुसार शेयर धारियों/प्रोत्साहकों/निदेशकों द्वारा उक्त नियर्यों का अनुमोदन किये जाने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे और साथ में उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने संबंधी विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

6.3 भारतीय पक्ष द्वारा संयुक्त उद्यम से अधिकारिक अधिकार पर जारी इकिटी शेयरों की अपनी हकदारियों के संबंध में अंशदान के मामले में अथवा संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्नों द्वारा जारी अतिरिक्त शेयर पूँजी में किसी भारतीय पक्ष द्वारा अंशदान किये जाने के मामले में, ऐसे अंशदान के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इस प्रकार के अंशदान के लिए अनुमति उपर्युक्त विवरानक 4.1 या 4.2 वैसी भी स्थिति हो, के अनुसार दो जांसकती है।

7.1 व्यापारिक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्नों स्थापित करने के मामलों में, मेजबान देश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली कम्नों द्वारा कार्यकलाप/इत्यादि/ग्राहकता के सम्बन्ध में संचालित किए जाने वाले प्रबलित एजेंसी प्रबन्धनों की भारतीय पक्ष द्वारा जब भी व्यवहार्य हो समीक्षा की जाएगी।

7.2 भारतीय पक्ष द्वारा किसी संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्नों को अपने इकिटी निवेश के संबंध में किए गये नियर्यों के लिए उसे कोई ऐसन्सी कमीशन नहीं देना होगा।

इसी प्रकार किसी व्यापारिक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कम्नों को अग्र भारतीय पक्ष उसे संधी विकी करता है तब भी कोई ऐसन्सी कमीशन देय नहीं होगा।

7.3 किसी संयुक्त उद्यम या पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्नों में सोधे निवेश करने वाला कोई भी भारतीय पक्ष भारत सरकार की पूर्व स्वोकृति के बिना संयुक्त उद्यम या पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कम्नों द्वारा लिए गए उधार अथवा छूट ग्राहि के संबंध में कोई गारंटी अथवा कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगा अथवा बाद में नहीं करेगा।

8. भारतीय पक्ष विदेशी कम्नों के संबंध में वाणिक कार्य निवादन रिपोर्ट के साथ-साथ वाणिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वाणिक लेखाओं की एक प्रमाणित प्रति वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा। ये दस्तावेज लेखा परीक्षित वाणिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने की मेजबान देश में प्रबलित वैद्यानिक अवधि समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जायेंगे। वैद्यानिक अवधि मेजबान देश के स्वतन्त्र संवादी/सार्वजनिक लेखाकार द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। यदि इस तरह की कोई वैद्यानिक अवधि न हो तो यह रिपोर्ट संगत लेखा परीक्षाः अवधि के समाप्त होने के लिए माह के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय पक्ष उक्त वाणिक रिपोर्ट के साथ विदेशी कम्नों से अग्री सभी हकदारियों और भारत को उनके प्रेषण का एक विस्तृत व्योरा भी प्रस्तुत करेगा।

9. भारतीय पक्ष को विदेशी कारोबार से राश्ली तकनीकी शुल्क प्रबंधन शुल्क या अन्दर प्रकार के भुगतान के रूप में जो भी रकम प्राप्त होनी है वह उक्ते देय होने की तारीख से 4 घंटीने के अन्दर मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत भेजेगा। भारतीय पक्ष को विदेशी कम्नों से जो भी लाभांश/कर प्रभावत लाभ प्राप्त होगा उसे वह विदेशी कम्नों के निवेशों/शेयरधारकों द्वारा व्योपित/अनुमोदित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के अन्दर मुक्त विदेशी मुद्रा में भारत भेजेगा। ऊपर बताये गये प्रेषण भेजबान देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रेषण की स्वेच्छा में लगाने वाले समय के अधिकारी होंगे।

इस पैरा में बतायी गई किसी हकदारी का प्रेषण यदि विदेशी कम्नों के अगले वित्तीय वर्ष के अन्दर भी पूरा नहीं किया गया तो भारतीय पक्ष वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें विदेशी कम्नों से प्राप्त होने वाली हकदारियों के नहीं भेजे जाने के कारणों का उल्लेख होगा।

10. जहां भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय राज्यिक को विदेशी कम्नों में निवेशक का पद स्वीकार करने की अनुमति दी गई है तो निवेशक का पद स्वीकार करने के पश्चात योग्यता शेयरों यदि कोई हो के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषण किसी भी भारतीय राज्यिक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये बिना एक बार में 500 अमरीकी डॉलर तक बैंकिंग प्रणाली के जरिए किया जा सकता है।

11. यदि भारतीय पक्ष को किसी मामले में प्रस्तुति विवेश के लिए या कम्नी अधिनियम के अन्तर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किये गये किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय पक्ष उपर्युक्त प्राधिकारियों से ऐसा अनुमोदन प्राप्त करेगा।

12. विदेश स्थित संयुक्त उम्मीदों या पूर्णस्वामित्र वाली सहायक कम्पनियों में किया गया समझा निवेश इन दिशा निर्देशों में विहित प्रावधानों के अध्ययन होगा, जहाँ वह इन दिशा निर्देशों के पैरा 4.1 या 4.2 के अन्तर्गत अनुमोदित भी रखो न हो। यदि कोई भारतीय पक्ष इन दिशा निर्देशों में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है या अनुमोदित पक्ष में निहित किसी शर्त को पूरा नहीं कर पाता है या केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा करता सार्वजनिक हित में है, तो केन्द्र सरकार, इस बारे में प्रत्यालित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही किये बिना, भारतीय पक्ष को नियन्त्रित समशावधि के भीतर अपनी शेयरखारिता बापस लेने या पूर्ण स्वामित्र वाली सहायक कम्पनी को बन्द करने और सभी प्राप्त अनुमति तथा अन्य हकदारियों को भारत भेजने का निर्देश दे सकते हैं।

जे एस. गिल संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1992

F. No. 4/11/91-EP(OI).—Guidelines for Indian direct investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad.

Government have revised the Guidelines for Indian direct investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad, which are hereby notified :

Guidelines for Indian Direct Investment in Joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad.

1.1 These guidelines shall apply to direct investment by Indian parties in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad (hereinafter referred to as "foreign concerns"). They apply to direct investment by Indian parties in newly promoted foreign concerns as well as to make initial or additional direct investment by Indian parties in existing foreign concerns.

1.2 The foreign concern in which the direct investment is proposed to be made may be engaged in industrial, commercial, trading or service activity or in hotel or tourism industry.

1.3 These guidelines do not apply to portfolio investment by Indian parties in foreign concerns. The guidelines do not also apply to direct investment in foreign concerns engaged in the financial sector such as banking, insurance, mutual funds, financial services and the like. Such cases would be considered on merits by the appropriate authority.

### 2. For the purposes of these guidelines,

(a) "direct investment" shall mean investment by an Indian party in the equity share capital of a foreign concern with a view to acquiring a long term interest in that concern. Besides the equity stake, such long term interest may be reflected through representation on the Board of Directors of the foreign concern and in the supply of technical know-how, capital goods, components, raw materials, etc. and managerial personnel to the foreign concern.

(b) "host country" shall mean the country in which the foreign concern receiving the direct investment is formed, registered or incorporated.

(c) "Indian party" shall mean a private or public limited company incorporated in accordance with the laws of India. When more than one Indian body corporate make a direct investment in a foreign concern, all the bodies corporate shall together constitute the "Indian party";

(d) "joint venture" shall mean a foreign concern formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country in which the Indian party makes a direct investment, whether such investment amounts to a majority or minority shareholding;

(e) "wholly owned subsidiary" shall mean a foreign concern formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country whose entire equity share capital is owned by an Indian party.

3. An application for direct investment in a foreign concern may be made by an Indian party in the prescribed form, supported by the prescribed documents, to the Ministry of Commerce (Overseas Investment Division), Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110001:

### 4.1 Category 'A'—Automatic Approval cases :

An application for direct investment in a foreign concern will be eligible for automatic approval within 30 days of the receipt of the application if either of the following two parameters is satisfied :

#### Parameter 1

The total value of the direct investment by the Indian party does not exceed US\$ 2 (two) million of which the subscription in cash by the Indian party does not exceed US \$500,000. The remainder of the direct investment may be contributed by the capitalisation in full or in part of—

(a) Indian made plant, machinery, equipment and components supplied to the foreign concern;

(b) the proceeds of goods exported by the Indian party to the foreign concern;

(c) fees, royalties, commissions or other entitlements from the foreign concern for the supply of technical know-how, con-

## PARAMETER 2

In case the direct investment by the Indian party consists solely of cash subscription, the cash subscription does not exceed US dollar 500,000.

4.1.1 This facility of automatic approval will be available to the Indian party in respect of the same foreign concern only once in a block of three financial years including the financial year in which the investment is made.

### 4.2 CATEGORY 'B'—OTHER CASES OR DIRECT INVESTMENT

All other cases of direct investment will be considered on merits by an Inter-Ministerial Committee in the Ministry of Commerce and a decision will be given within 90 days of the receipt of the application. Besides the sources of investment indicated in Category 'A' above, the direct investment under Category 'B' may include the following sources also :

- (a) external borrowings subject to approval by the appropriate authorities;
- (b) payment out of "blocked" funds. Blocked funds arise when receivables from exports to or returns from investments made in a host country are not transferred to an Indian party due to reasons beyond the control of the Indian party;
- (c) any other source of investment that may be permitted by the Government of India.

4.3 In considering an application under Category 'B', the Inter-Ministerial Committee shall, *inter alia*, have due regard to the following :

- (a) The financial position, standing and business track record of the Indian and foreign parties;
- (b) Experience and track record of the Indian party in exports and its external orientation;
- (c) Prima facie viability of the proposed investment;
- (d) Quantum of the proposed investment and the size of the overseas venture in the context of the resources, net worth and scale of operations of the Indian party; and
- (e) Benefits to the country in terms of foreign exchange earnings, two way trade generation, technology transfer, access to raw materials and intermediates not available in India, and the like.

4.4 Both under Categories 'A' and 'B' above, second hand or reconditioned indigenous machinery may be supplied by the Indian party towards its contribution to the direct investment in the foreign concern.

5. The direct investment shall conform to the laws and regulations of the host country. It is desirable to associate, to the extent possible, local parties, local

development banks, and local financial institutions in a joint venture. Unless there are strong reasons to the contrary, the association of individuals as foreign promoters or partners is not encouraged.

6.1 In the case of a joint venture in which the Indian party has a minority equity shareholding, the Indian party shall report to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India the details of the following decisions taken by the joint venture within 30 days of the approval of those decisions by the shareholders/promoters/Directors of the joint venture in terms of the local laws of the host country :

- (i) Undertake any activity different from the activity originally approved by the Government of India for the direct investment;
- (ii) Participate in the equity capital of another concern;
- (iii) Promote a subsidiary or a wholly owned subsidiary as a second generation foreign concern;
- (iv) Alter its share capital structure, authorised or issued, or its shareholding pattern.

6.2 In the case of a joint venture in which the Indian party has a majority equity shareholding or in the case of a wholly owned subsidiary, the Indian party may, without prior reference to the Government of India, consent to the following decisions being taken by the foreign concern :

- (i) Undertake any activity different from the activity originally approved by the Government of India for direct investment;
- (ii) Participate in the equity capital of another concern;
- (iii) Promote a subsidiary or a wholly owned subsidiary as a second generation foreign concern;
- (iv) Alter its share capital structure, authorised or issued, or its shareholding pattern.

Provided, the following conditions are fulfilled :

- (a) the Indian party has repatriated all entitlements due to it from the foreign concern, including dividends, fees and royalties and this is duly certified by a Chartered Accountant;
- (b) the Indian party has no overdues older than 180 days from the foreign concern in respect of its exports to the latter;
- (c) the Indian party does not seek any fresh cash remittance from India; and
- (d) the percentage of equity shareholding of the Indian party in the first generation joint venture or wholly owned subsidiary is not reduced, unless it is pursuant to the laws of the host country.

The Indian party shall report to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India the details of the decisions taken by the joint venture or the

wholly owned subsidiary within 30 days of the approval of those decisions by the shareholders|promoters| Directors in terms of the local laws of the host country together with a statement on the fulfilment of the conditions mentioned above.

6.3 In the case of subscription by an Indian party to its entitlement of equity shares issued by a joint venture on Right's basis, or in the case of subscription by an Indian party to the issue of additional share capital by a joint venture or a wholly owned subsidiary, prior approval of the Government of India shall be taken for such subscription. Approval for such subscription may be given in accordance with paragraph 4.1 or 4.2 above, as the case may be.

7.1 In cases of setting up of trading joint ventures or wholly owned subsidiaries, the existing agency arrangements in the host country in respect of the activity|product|territory to be dealt with by the joint venture|wholly owned subsidiary shall be reviewed by the Indian party as soon as practicable.

7.2 No agency commission shall be payable to a joint venture|wholly owned subsidiary against the exports made by the Indian party towards its equity investment. Similarly, no agency commission shall be payable to a trading joint venture|wholly owned subsidiary if the Indian party makes an outright sale to it.

7.3 The Indian party making a direct investment in a joint venture or a wholly owned subsidiary shall not, except with the prior approval of the Government of India, give any guarantee or undertake any financial liability or commitment in respect of any loan, credit, etc. raised by the joint venture or the wholly owned subsidiary.

8. The Indian party shall furnish to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India an annual performance report in respect of the foreign concern, together with a certified copy of its Annual Report and audited annual accounts, within 30 days of the expiry of the statutory period for finalisation of audited annual accounts applicable in the host country. The statutory period should be certified by an independent Chartered|Public Accountant of the host country. In case there is no such statutory period, the report shall be submitted within six months of the close of the relevant accounting period. Together with the annual performance report, the Indian party shall also furnish a detailed statement of all the en-

titlements due to it from the foreign concern and their remittance to India.

9. The Indian party shall remit to India in free foreign exchange all entitlements due to it from a foreign concern by way of royalty, technical fees, management fees or any other type of payments within a period of 60 days from the date they become due. The Indian party shall remit to India in free foreign exchange dividends|profit after tax due to it from a foreign concern within a period of 60 days from the date they are declared|approved by the Directors|shareholders of the foreign concern. The remittances mentioned above shall be subject to the time taken for clearance of the remittances by the central bank of the host country. In case the remittance of any entitlement mentioned in this paragraph has not been completed even within the following financial year of the foreign concern, the Indian party shall furnish a special report to the Ministry of Commerce and the Reserve Bank of India explaining the reasons for non-remittance of the entitlements due to it from the foreign concern.

10. Where an Indian national is permitted by the Government of India to accept Directorship in a foreign concern, remittance of foreign exchange for acquisition of qualification shares, if any, pursuant to acceptance of a Directorship, may be effected by an Indian national through banking channels upto US dollar 500 in a single instance without reference to the Reserve Bank of India.

11. In any case where the Indian party requires approval under the Companies Act or any other law for the time being in force for the proposed direct investment, the Indian party shall obtain such approval from the appropriate authorities.

12. All direct investment in joint ventures and wholly owned subsidiaries abroad, whether approved under paragraph 4.1 or 4.2 of these guidelines, is subject to the provisions contained in these guidelines. If an Indian party violates any provision of these guidelines or fails to fulfil any of the conditions contained in the letter of approval, or if the Central Government is satisfied that it is in public interest to do so, the Central Government may, without prejudice to any action under any other law applicable to the case, direct the Indian party to disinvest its shareholding or wind up the wholly owned subsidiary and remit all proceeds and other entitlements to India within a stipulated period.

J. S. GILL, Lt. Secy.